Gandhamardan Hill Region, I urge the Government to declare and designate it as a biosphere reserve. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN:The hon. Member, Smt. Mamata Mohanta (Odisha), associated herself with the matter raised by the hon. Member Shri Sujeet Kumar.

Now, Shri K.R.N Rajeshkumar — Demand for increase in wheat allocation to Tamil Nadu; not present. Dr. John Brittas — Demand to assist Kerala in rehabilitating landslide victims in Wayanad District; not present. Shri Neeraj Dangi — Demand for removal of 18 per cent GST on insurance policy for senior citizens; not present. Shri Manoj Kumar Jha — Need for enhancement of honorarium for ASHA workers; not present. Now, Shri Satnam Singh Sandhu.

Increasing cases of grabbing NRIs' properties in our country

श्री सतनाम सिंह संधू (नामनिर्देशित) : उपसभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैं 3.5 करोड़ से ज्यादा प्रवासी भारतीयों से जुड़ा एक बहुत ही अहम मुद्दा सदन के सामने रखना चाहता हूं।

उपसभापति जी, देश के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर विकसित भारत की यात्रा तक हमारे प्रवासी भारतीयों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। देश के स्वतंत्रता संग्राम को जो मदद बाहर से मिली, हमारे प्रवासी भारतीयों से मिली, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है और आज विकसित भारत की यात्रा में भी प्रवासी भारतीयों का योगदान बहुत अहम है। महोदय, शायद इसीलिए हमारे देश के प्रधान मंत्री प्रवासी भारतीयों को राष्ट्रदूत कहते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। महोदय, हमारे लिए यह गर्व की बात है कि अब प्रवासी भारतीय ग्लोबल लेवल पर बहुत ही प्रभावशाली भूमिका निभा रहे हैं और देश की प्रगति के लिए खूब धन भी भेज रहे हैं। उपसभापति महोदय, यू.के. में हुए रिसेंट पार्लियामेंट इलेक्शन्स में भारतीय मूल के 29 सांसद निर्वाचित हुए हैं। मैं समझता हूं कि यह भारत के लिए एक गर्व की बात है। उस देश में, जिसने हमें लंबे समय तक गुलाम बनाकर रखा, आज उसके दोनों सदनों में भारतीयों की गिनती करीब 40 के लगभग हो गई है, जिसके लिए मैं समझता हूं कि यह भारत की बढ़ती हुई सॉफ्ट पॉवर की एक बहुत बड़ी मिसाल है।

उपसभापति जी, देश से हज़ारों मील दूर रहने के बावजूद भी प्रवासी भारतीयों का दिल भारत के लिए धड़कता है, देश से जुड़े रहने के लिए उन्होंने अपने घर और संपत्तियाँ नहीं बेची हैं और अपने देश में नये निवेश भी कर रहे हैं, लेकिन इसके चलते प्रवासी भारतीयों की संपत्तियों पर नाजायज कब्ज़े और धोखाधड़ी के अनगिनत मामले सामने आ रहे हैं। महोदय, इसकी वजह से प्रवासी भारतीयों के अंदर अपनी संपत्तियों को लेकर एक डर का माहौल पैदा हो रहा है और वे बाहर से अपनी संपत्तियों को बेचने को तरज़ीह दे रहे हैं। उपसभापति जी, यह बहुत ही गंभीर मामला है। इसकी गंभीरता केवल संपत्तियों का बेचा जाना ही नहीं है, बल्कि मातृभूमि से उनके संबंधों का टूटना या कमजोर होना भी है।

उपसभापति जी, प्रवासी भारतीयों की संपत्तियों की प्रोटेक्शन एन्श्योर करने के लिए आज एक नई व्यवस्था बनाने की आवश्यकता नज़र आ रही है, जिसमें प्रवासी भारतीयों की कांफिडेंस बिल्डिंग की जा सके। इस व्यवस्था के तहत संपत्तियों की मैपिंग करके उन्हें सिक्योर किया जाए, जिससे उन संपत्तियों पर कोई भी कब्ज़ा न कर पाए। कब्ज़ा न होने की सूरत में सरकार एक वन स्टेप...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The hon. Member, Shri Sujeet Kumar (Odisha) associated himself with the matter raised by the hon. Member, Shri Satnam Singh Sandhu. Now, Question Hour.

12.00 **Noon**

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Prime Minister's Employment Generation Programme

*166. MS. INDU BALA GOSWAMI: Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether any financial assistance is provided to unemployed youth to start a business under Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP);

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether there is a provision of granting loan to start own business under the said Programme, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SHRI JITAN RAM MANJHI): (a) to (c) A statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) to (c)To assist prospective entrepreneurs including unemployed youth in setting up of new enterprises in the non-farm sector, financial assistance is provided in the form of Margin Money (MM) subsidy on the project cost under the Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) being implemented by Ministry of MSME, through Khadiand Village Industries Commission (KVIC).

The categories of beneficiaries, applicable subsidy rates and percentage of contribution under PMEGP is given below: